सोशल मीडिया से

चेहरे पर फेसबुक सी रौनक है,
दिल व्हाट्सप्प हुआ जा रहा है।
समाज से कटकर भी,
इंसान सोशल हुआ जा रहा है

सच कहने की ताकत

जालंधर ब्रीज

साप्ताहिक समाचार पत्र

RNI NO.:PUNHIN/2019/77863

अनमोल विचार

घमण्ड के अंदर सबसे
बुरी बात यह होती है
की वो आपको
कभी महसूस
होने नहीं देगा की
आप गलत हो

• JALANDHAR BREEZE • WEEKLY •YEAR-1 • EDITOR: ATUL SHARMA • 23 OCTOBER TO 29 OCTOBER 2019 • VOLUME-11• PAGES- 4 • RATE- 3/- • Mobile: 99881-15514 • email:atul_editor@jalandharbreeze.com

हम तो दूध के धुलें हैं सारा कसूर तो जिला प्रशासन का है

■ जालंधर से प्रभातपुरी की विशेष रिपोर्ट

नैशनल हाईवे विभाग जिस का कि प्रमुख हाईवे एन एच 44 उनके द्वारा बनाया गया है। पिछले दिनों जालंधर ब्रीज द्वारा जालंधर पठानकोट हाईवे पर हो रहे हादसों पर चिंता व्यक्त की गई थी और इस पर मनिस्ट्री में भी शिकायत दर्ज करवाई गई थी पर अपनी सफाई में विभाग द्वारा जानकारी के लिए लैटर न. मोंथ /ईय2019/03352 दर्ज अपने जवाब में दर्शाया गया है जिसमें कि तंग हाईवे के जवाब में विभाग द्वारा ये जवाब दिया गया है कि 2010 से लेकर 2014 के बीच जो भी निर्माण करवाया गया है वो पास नक्शों के हिसाब से ही बनाया गया है।

अब वो चाहे तंग बन गया है जो अनाधिकृत कब्जे हाईवे पर करवाये गये है वो विभाग द्वारा समय-समय पर पुलिस और जिला प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से इनको हटाया गया है और हमारे ठेका प्राप्त कंपनी द्वारा इसको हटाने के लिए जो जब मौके पर टीम भेजी गई उनका कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा घेराव किया गया और कब्जों को गिराने से रोका गया।

इन सभी मुद्दों को हमारे द्वारा अपने विभाग की तरफ से पत्र लिखकर जारी किया जायेगा जिसमें एस.एस.पी. और जिलाधीश को लिखकर उनसे मदद मांगी जाएगी। जो हाईवे पर रेलिंग टूटी है वो ठेका प्राप्त कंपनी द्वारा उसे समय-समय पर ठीक करवाया गया है परंतु मौके पर मौजूद दुकानदारों द्वारा इसे अपनी सुविधा के लिए तोड़ दिया जाता है। जो पानी की समस्या हाईवे पर है उसके लिए विभाग द्वारा जिम्मेदार नगर निगम को ठहराया गया है जिस में उसने अपने जवाब में ये बताया है कि नगर निगम द्वारा मौके पर मौजूद दुकानदार, उद्योगिक घराने, ढाबे व अन्य लोगों द्वारा हमारी नाली में अपने गंदे पानी की पाईप डाल दी गई है जिस कारण नालीयां बंद हो जाती है ओर हाईवे पर पानी जमा हो जाता है। इन सारे वाक्यों से ऐसे प्रतीत हो रहा है विभाग ये सिद्ध करना चाह रहा है कि हम तो दूध के धुलें है सारी गलती जिला प्रशासन की है और अपने पत्र द्वारा जिला प्रशासन को गलत साबित कर रहे है।

जो पानी की समस्या हाईवे पर है उसके लिए विभाग द्वारा जिम्मेदार नगर निगम को ठहराया गया है जिस में उसने अपने जवाब में ये बताया है कि नगर निगम द्वारा मौके पर मौजूद दुकानदार, उद्योगिक घराने, ढाबे व अन्य लोगों द्वारा हमारी नाली में अपने गंदे पानी की पाईप डाल दी गई है

कहानी का तेरी मैंने यक़ीं तो कर लिया लेकिन हकीकत एक दिन फिर से तेरी आँखों से पूछूँगा

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways)
PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU)
778, KALIA COLONY, NEAR VK KALIA PUBLIC SCHOOL
JALANDHAR -144008 (PUNJAB)

No: FD/PIU Jal/180-A/Complaint/2019/3560 Date: 10.10.2019

To,
Sh. Atul Sharma
NN- 451, Gopal Nagar,
Jalandhar
(M) 9988115514

Sub: Grievance no. MORTH/E/2019/03552 of Sh. Atul Sharma- reg.

Sir,

Please refer to your online grievance received through Online PG portal vide registration no. MORTH/E/2019/05216 on the above mentioned subject.
It is intimated that the matter was forwarded to IE of the Project and IE stated that:

1. Highways was constructed in accordance with approved drawings/ TCS during the original construction (2010 to 2014)
2. The notices are issued to the encroachers under the land act 2002 and time to time encroachment removal drives are organize in association with local authorities and police. In this regard, we would like to inform, temporary vegetable, fruit shops were established on cover drain. Moreover, team of concessionaire along with consultant went to remove encroachment but was heckled by a group of people during anti encroachment drive as such people are patronised by influential personalities. Considering this, we request authority to write a letter to SSP and DC of the respective town falling along the highway as Jalandhar, Hoshiyarpur, Pathankot, Kangra (Himachal) in procuring police & local administration assistance to remove encroachment as cited above.
3. Damaged PGR Railing were rectified from time to time which is the part of maintenance obligation of the Concessionaire above that huge length of missing PGR railing were also got installed from the concessionaire. Further, the fact need to be taken into considerations that at many locations PGR is removed by the owner of various shop keepers in order to facilitate their business that also we are getting repaired under routine maintenance.
4. Blockage of Lined drain – Urban Area: In this regard, we would like to notify, cover drain along the service road was designed and constructed for the removal of rainwater/surface water from the road surface. Moreover, we would like to draw your attention to the silent facts that, establishments like industries, shops, dhabas, hawkers etc had connected their waste pipe directly with highway drain and result in blockage frequently. We further request authority to put up above concern in front of MC which is acting as silent observer.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways)
PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU)
778, KALIA COLONY, NEAR VK KALIA PUBLIC SCHOOL
JALANDHAR -144008 (PUNJAB)

5. Unified guidelines for Access permission to fuel stations, Private properties, Rest areaComplexes, and such other facilities along National Highway is formulated and notified vide Ministry's guidelines Circular letter No:- RW/NH—33023/19/99-DO-III; dated 24.07.2013 and the corrigendum issued by the Ministry MoRT&H letter No:- RW/NH—33023/19/99-DO-III; dated 25.08.2014 and the fourth revision is issued vide IRC-12-2016". These provisions are universally applicable in all states of India uniformly.

Project Director
PIU, Jalandhar

सरकारी विभाग

सरकारी विभागों में अदालत केसों के लिए कमेटीयां क्यों नहीं गठित की जाती

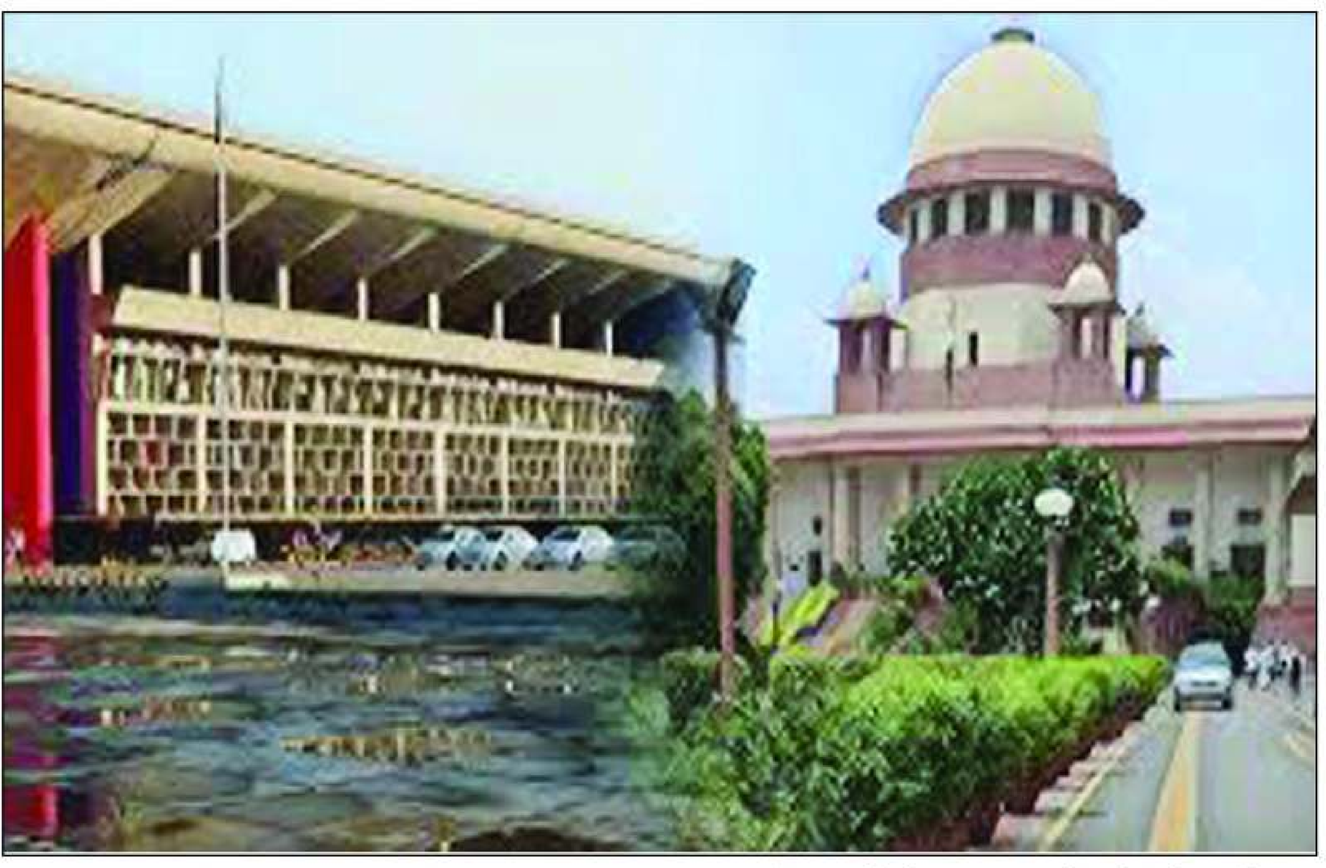

प्रमुख विभाग नगर निगम, पुड़ा, तहसील जैसे विभागों में देखने में मिलता है कि आप किसी काम के लिए इन में से किसी भी दफ्तर में जाते हो और आप ड्यूटी अफसर के बारे में पूछते हो तो आपको सुनने में मिलता है कि वो कोर्ट में है।

■ जालंधर से प्रभातपुरी की विशेष रिपोर्ट

राज्य की या केन्द्र की सरकार द्वारा रोज़ाना अपने अफसरों को लिटिकेशन में व्यस्त रखना लोगों के लिए सिद्ध हो रहा है घातक। अमूमन देखने को मिलता है कि विभागों के कोई ना कोई अफसर ड्युटी के दौरान कोर्ट केसों में व्यस्त रहता है जिससे की आम लोगों के लिए बड़ी असुविधा है। जिसमें कि प्रमुख विभाग नगर निगम, पुड़ा, तहसील जैसे विभागों में देखने में मिलता है कि आप किसी काम के लिए इन में से किसी भी दफ्तर में जाते हो और आप ड्यूटी अफसर के बारे में पूछते हो तो आपको सुनने में मिलता है कि वो कोर्ट में है। जो बहुत ही लोगों को गैर जिम्मेदराना जवाब लगता है। अगर किसी अफसर को उसके प्रमुख अफसर द्वारा किसी कोर्ट केस में भेजना है तो उसकी जगह प्रमुख अफसर की ड्युटी बनती है कि किसी दूसरे अफसर को उसका कामकाज देखने के लिए नियुक्त किया जाए। परंतु कई विभागों में ऐसा किया भी जाता है पर जिस अफसर की नियुक्ति की जाती है वो उस दिन किसी कागज पर हस्ताक्षर नहीं करता वो इस बात से डरता है कि एक दिन के चक्कर में वो किसी गलत कागज पर हस्ताक्षर ना कर दें। इस से अफसरों का कोई नुकसान हो नहीं रहा परंतु लोग हाशीये पर चले जाते है क्योंकि उनको बार-बार उस अफसर के दफतर के चक्कर लगाने पड़ते है। इसलिए प्रमुख सक्तर पंजाब को दिशा निर्देश देने चाहिए कि हर विभाग लीगल अफसर की ओर एक प्रशासनिक अधिकारी की देख रेख में कमेटी गठित करे। जिस में संबंधित विभाग का कोई भी अदालत केस चाहे वो निचली अदालतों में हो, चाहे वो जनहित याचिकायें पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में हो इन सभी कोर्ट केसों के लिए कमेटी द्वारा वकीलों से संपर्क साधा जाये और लोगों को इस रोज के अफसरों के बहाने से राहत मिल सके।

दिल्ली की सड़कों को री-डिजाइन करेगी केजरीवाल सरकार

■ नई दिल्ली/न्यूज नेटवर्क

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली सरकार उन सभी सड़कों का ढांचा और डिजाइन बदलेगी जिनकी देखरेख लोक निर्माण विभाग करता है। मुख्यमंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पहले चरण में सरकार ने नौ सड़कों का चयन किया है। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी के तहत जिन सड़कों की देखरेख का काम आता है, उन सभी सड़कों का डिजाइन अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप किया जाएगा। सड़कों का ढांचा भी बदला जाएगा और मोटरविहीन वाहनों तथा दिव्यांग लोगों के आनेजाने के लिए जगह बनाई जाएगी।

परियोजना की लागत करीब 400 करोड़ रुपए होगी और इससे सड़क की उपयोगिता और क्षमता में इजाफा होगा। पहले चरण में जिन सड़कों का चयन किया गया है वह हैं एम्स से आश्रम और विकास मार्ग (लक्ष्मी नगर चुंगी) से लेकर कड़कड़डूमा तक के मार्ग।

मोदी सरकार 5 वर्षों में "हुनर हाट" के जरिए लाखों लोगों को रोजगार मुहैया कराएगी : नकवी

■ नई दिल्ली/न्यूज नेटवर्क

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को कहा कि अगले 5 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार "हुनर हाट" के माध्यम से "हुनर के उस्ताद" लाखों कारीगरों, शिल्पकारों, दस्तकारों और पारंपरिक खानसामों को रोजगार तथा रोजगार के मौके मुहैया कराएगी। नकवी ने यह भी कहा कि अगला "हुनर हाट" प्रयागराज में आगामी एक से 10 नवम्बर के बीच आयोजित किया जायेगा। प्रयागराज में आयोजित किये जा रहे देश भर के हुनर के उस्तादों के मेले में बड़ी संख्या में महिला कारीगरों सहित देश के हर कोने से 300 से अधिक दस्तकार, शिल्पकार, खानसामे भाग लेंगे। 2019-2020 के सभी "हुनर हाट", "एक भारत श्रेष्ठ भारत" के थीम पर आधारित होंगे। उन्होंने कहा, " पिछले तीन वर्षों में देश के प्रसिद्ध आर्थिक केंद्रों में आयोजित एक दर्जन से ज्यादा "हुनर हाट" के जरिये 2 लाख 50 हजार से ज्यादा कारीगरों, शिल्पकारों, दस्तकारों, खानसामों और उनसे जुड़े हुए लोगों को रोजगार और रोजगार के मौके मुहैया कराये गए हैं जिनमे बड़ी संख्या में महिला कारीगर भी शामिल हैं।" मंत्री ने कहा, " अगले 5 वर्षों में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय देश के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 100 "हुनर हाट" का आयोजन करेगा। आने वाले दिनों में "हुनर हाट" का आयोजन दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, अहमदाबाद, देहरादून, पटना, इंदौर, भोपाल, नागपुर, रायपुर, हैदराबाद, पुडुचेरी, चंडीगढ़, अमृतसर, जम्मू, शिमला, गोवा, कोच्चि, गुवाहाटी, रांची, भुवनेश्वर, अजमेर आदि में किया जायेगा।" नकवी ने कहा कि "हुनर हाट" में आने वाले दस्तकारों, शिल्पकारों का सशक्तिकरण तो हो ही रहा है साथ ही प्रत्येक दस्तकार, शिल्पकार के साथ कम से कम 40 से 50 लोग जुड़े होते हैं जिन्हें रोजगार के मौके मिलते हैं। इन सभी दस्तकारों, शिल्पकारों को अपने स्वदेशी हस्तनिर्मित उत्पादन को राष्ट्रीय-अंतरर्राष्ट्रीय मार्किट मुहैया होते हैं। मंत्री ने कहा कि "हुनर हाट", दस्तकारों/शिल्पकारों का "एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज" साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि दस्तकारों, शिल्पकारों को मौका-मार्किट मुहैया कराने के मिशन के तहत देश के विभिन्न भागों में आयोजित "हुनर हाट" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "मेक इन इंडिया", "स्टैंड अप इंडिया", "स्टार्ट अप इंडिया" के संकल्प को साकार करने का "प्रामाणिक एवं विश्वसनीय ब्रांड" बन गया है। साथ ही "हुनर हाट", "एक भारत श्रेष्ठ भारत" के संकल्प को शक्ति दे रहा है।"

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया, देश में इतने लोगों की सैलरी है 100 करोड़ रुपये से भी ज्यादा

■ नई दिल्ली/न्यूज नेटवर्क

देश में मंदी और आर्थिक संकट को लेकर एक ओर बहस जारी है तो वहीं दूसरी ओर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जानकारी दी है कि भारत में ऐसे 9 लोग हैं जिनकी सैलेरी 100 करोड़ से ज्यादा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आकड़ों के अनुसार देश में वित्तीय वर्ष 2017-18 में 100 करोड़ रुपये से अधिक सैलेरी पाने वाले 9 लोग हैं। वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की माने तो 500000 लोग सालाना एक करोड़ से ज्यादा सैलरी पाते है। हालांकि कोई भी व्यक्ति देश में 500 करोड़ के सैलरी वाले स्लैब में नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये आंकड़े इनकम टैक्स रिटर्न के आधार पर जारी किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार 2.9 करोड़ वेतनभोगी टैक्सपेयर्स में से 81.5 लाख लोगों की सैलरी 5.5 लाख रुपये से लेकर 9.5 लाख रुपये के बीच है. वहीं 22 लाख से अधिक लोग 10-15 लाख की सैलरी स्लैब में हैं। इसके अलावा 15 से 20 लाख के स्लैब में सात लाख लोग है, 20 से 25 लाख के स्लैब में 3.8 लाख लोग हैं, 25 से 50 लाख के स्लैब में पांच लाख लोग है, 50 लाख से एक करोड़ से स्लैब में 1.2 लाख लोग हैं. वहीं एक करोड़ रुपये से अधिक की सैलरी लेने वालों की संख्या 49,128 है, जिनमें से केवल नौ लोगों की सैलरी 100 करोड़ रुपये से अधिक है।

खुला मंच

● विचारधारा ● चिंतन-मंथन ● दृष्टिकोण

ट्विटर

महाराष्ट्र और हरियाणा में भाजपा की नाकामी के खिलाफ वोटिंग हुई है। दोनों ही राज्यों में भाजपा के काम को जनता ने नकारा है और यह 24 को दिखेगा भी।

- मनीष तिवारी, कांग्रेस नेता

उक्ति

"छोटी-छोटी सफलताएं ही अंत में हमें बड़ी सफलताएं हासिल करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसलिए छोटी सफलताओं का सम्मान करो, उन्हें पाने के बाद जश्न मनाओ।

- रान्डा वर्न्स

दखल

अयोध्या के फैसले की घड़ी

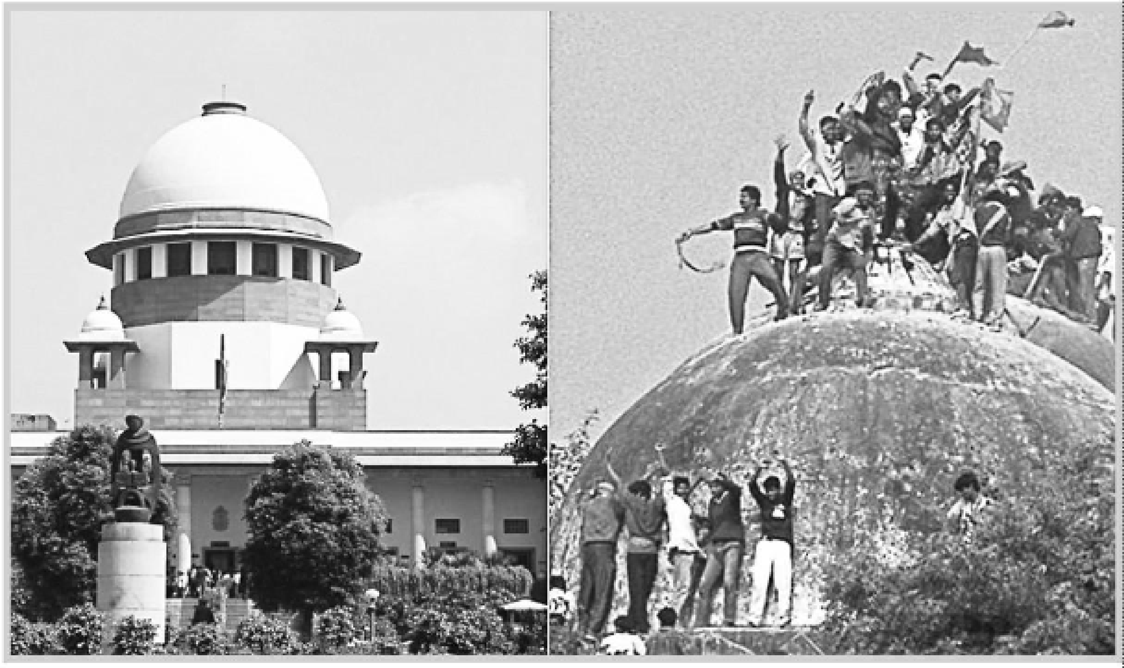

दशकों पुराने अयोध्या विवाद मामले में फैसले की घड़ी नजदीक आ गई। उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय नवंबर के मध्य तक फैसला सुना देगा। अब जबकि अदालत का फैसला आने में कुछ दिन ही शेष है। ऐसे में आवश्यक है कि देश धैर्य का परिचय दे। फैसला जो भी आए उसे दोनों पक्ष स्वीकार करें। किसी तरह का उन्माद या फिर हिंसा देश की गंगा-जमुनी तहजीब को नष्ट करेगी और कोर्ट का विश्वास भी डिगेगा।

दशकों पुराने अयोध्या विवाद मामले में फैसले की घड़ी नजदीक आ गई। मध्यस्थता के जरिए विवाद सुलझाने की सभी कोशिशें विफल होने के बाद जिस तरह सर्वोच्च अदालत ने सभी पक्षकारों को नियत समय में पक्ष प्रस्तुत करने को कहा और लगातार 40 दिन तक सुनवाई की उसी का प्रतिफल है कि दशकों पुराना विवाद अब सुलझने के कगार पर है। उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय नवंबर के मध्य तक फैसला सुना देगा। गौरतलब है कि इस मसले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचुड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने की है। संविधान पीठ ने मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट देखने के बाद रोजाना सुनवाई का निर्णय लिया। गौरतलब है कि अदालत ने अयोध्या विवाद को अदालत से बाहर मध्यस्थता के जरिए सुलझाने को कहा था। इसके लिए तीन मध्यस्थ नियुक्त किए, जिनमें जस्टिस एफएम इब्राहिम कलीफुल्ला मध्यस्थता समूह के अध्यक्ष थे। उनके अलावा दो अन्य सदस्यों में आध्यात्मिक गुरु श्रीश्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील एवं मध्यस्थता संबंधी मामलों के विशेषज्ञ श्रीराम पंचू शामिल थे।

तब अदालत ने मध्यस्थता समूह को आठ सप्ताह का वक्त देते हुए चार सप्ताह के दरम्यान प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। मध्यस्थता पैनल के अनुरोध पर सर्वोच्च अदालत ने 15 अगस्त तक समय बढ़ा दिया, लेकिन इसी बीच मुख्य मुकदमे के पक्षकार गोपाल सिंह विशारद ने नौ जुलाई को सर्वोच्च अदालत में अर्जी दाखिल कर कहा कि मध्यस्थता में कुछ ठोस प्रगति नहीं हुई और इससे विवाद का हल निकलने की उम्मीद नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च अदालत ने मध्यस्था पैनल से रिपोर्ट मांगी। ऐसा नहीं है कि मध्यस्थता पैनल ने राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक रूप से अति संवेदनशील इस मसले पर सहमति बनाने की कोशिश नहीं की। उसने समाज के सभी वर्गों के जिम्मेदार लोगों से बातचीत की और हर संभावनओं को टटोलने का प्रयास किया। लेकिन नतीजे उत्साहजनक नहीं रहे।

लिहाजा मध्यस्थता पैनल ने अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च अदालत को सौंप दी। फिर उसे देखने के बाद सर्वोच्च अदालत इस नतीजे पर पहुंचा कि मध्यस्थता प्रक्रिया के जरिए विवाद का हल संभव नहीं है। ऐसे में उसके पास सुनवाई के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। हालांकि यह पहले से अनुमान था कि इस मसले का हल मध्यस्थता के जरिए संभव नहीं है। इसलिए कि मुस्लिम पक्षकारों द्वारा इसका लगातार विरोध जताया गया। जमीयत-ए-उलेमा हिंद ने अदालत के मध्यस्थता के सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया। इसी तरह बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी ने कहा कि वे अदालत के बाहर समझौता को तैयार नहीं हैं। उधर, हिंदू संगठनों ने बातचीत का तो स्वागत किया लेकिन उनका भी स्पष्ट मानना था कि चूंकि पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम का जन्म अयोध्या में हुआ लिहाजा जमीन भी रामलला की ही है। ऐसे में समझौते का कोई मतलब नहीं है। याद होगा जब इस मसले पर 30 सितंबर, 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला आया तब भी दोनों पक्षों के बीच एक बेहतरीन नतीजे पर पहुंचने की उम्मीद थी। लेकिन कुछ सियासी दलों और मजहबी संगठनों ने ऐसा नहीं होने दिया।

मध्यस्थता पैनल की लाख कोशिश के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। उसका महत्वपूर्ण कारण सिर्फ यह था कि बाबरी मस्जिद के पैरोकार किसी भी कीमत पर रामजन्म भूमि पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं थे। जबकि वे इस तथ्य से भलीभांति अवगत रहे कि 30 सितंबर, 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट कहा गया कि जहां रामलला की मूर्ति स्थापित है, वहां के मालिक रामलला ही हैं न कि कोई और। उसके बावजूद भी मुस्लिम पक्षकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफसुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से बाज नहीं आए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद हिंदू पक्षकारों में भी इस बात पर विमर्श तेज हो गया कि जब न्यायालय द्वारा विवादित जमीन रामलला का ही माना गया है तो फिर उसे तीन हिस्सो में बांटने का क्या औचित्य है। लिहाजा रामलला के पैरोकार भी सर्वोच्च अदालत पहुंच गए। चूंकि अब मामले की सुनवाई सर्वोच्च अदालत में पूरी हो गई है ऐसे में माना जा रहा है कि संविधान पीठ के अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नवंबर को सेवानिवृत हो रहे हैं उससे पहले फैसला आ जाएगा।

जानकारों का कहना है कि सर्वोच्च अदालत में सामान्य तौर पर जब किसी मामले की नियमित सुनवाई होती है तो फिर जो पीठ सुनवाई कर रही होती है वही पीठ सुनवाई करके फैसला सुनाती है। आमतौर पर बीच में सुनवाई पीठ को बदलने की परंपरा नहीं रही है। अच्छी बात यह रही कि अदालत इस मामले में लेटलतीफी को तैयार नहीं था अन्यथा मुस्लिम पक्षकारों ने मामले को उलझाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन अदालत ने सुनिश्चित कर दिया कि अब किसी तरह का घालमेल नहीं चलेगा। उसने सुनवाई की शुरुआत मूल वाद संख्या तीन और पांच से की। गौरतलब है कि मूल वाद संख्या तीन निर्मोही अखाड़ा का मुकदमा है व मूल वाद संख्या पांच भगवान रामलला विराजमान का मुकदमा है। अदालत ने मामले के वकीलों और पक्षकारों से दो टूक कहा कि जिन साक्ष्यों और दलीलों को वे अदालत में पेश करने वाले हैं उसके बारे में पहले ही बता दें ताकि अदालत स्टॉफ उसे पेश करने के लिए तैयार रखे। दरअसल सर्वोच्च अदालत नहीं चाहता था कि साक्ष्यों को लेकर देरी हो।

यहां जानना आवश्यक है कि 30 सितंबर, 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अयोध्या मामले को लेकर चल रहे मालिकाना हक से संबंधित चार वादों पर अपना निर्णय दिया था। निर्णय के अनुसार विवादित 2.77 एकड़ जमीन को तीन हिस्सों में बराबर-बराबर बांटी जानी थी। अर्थात एक तिहाई जमीन रामलला को दी जानी थी जिनका पैरोकारी हिंदू महासभा द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह एक तिहाई जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड और इतनी ही जमीन निर्मोही अखाड़ा को दी जानी थी। इसी निर्णय को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तीनों न्यायाधीशों के फैसले पर नजर दौड़ाएं तो न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा ने फैसले में कहा था कि वह 12 वीं शताब्दी के राममंदिर को तोड़कर बनाया गया। न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने कहा कि वह किसी बड़े हिंदू धर्मस्थल को तोड़कर बनाया गया। न्यायमूर्ति खान ने भी कहा कि वह किसी पुराने ढांचे पर बना था। इन विद्वान न्यायाधीशों के फैसले से स्पष्ट हो गया था कि वहां राममंदिर ही था जिसे तोड़कर मस्जिद का स्वरूप दिया गया। इन विद्वान न्यायाधीशों के अलावा 2003 में विवादित स्थान की खुदाई से भी कई सामग्रियां प्राप्त हुई जिसे अदालत के समक्ष रखा गया।

ध्यान देना होगा कि विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद आज भी भगवान श्रीराम कारसेवकों द्वारा तिरपाल के अस्थायी मंदिर में रह रहे हैं। यह तिरपाल का मंदिर उसी स्थान पर है जहां विध्वंस से पहले रामलला विद्यमान थे। अब अदालत का फैसला आने में कुछ दिन ही शेष है। ऐसे में आवश्यक है कि देश धैर्य का परिचय दे। फैसला जो भी आए उसे दोनों पक्ष स्वीकार करें।

■ अरविंद जयतिलक
(वरिष्ठ पत्रकार)

विशेष संपादकीय

चुनाव बताएंगे देश का मूड

लोकसभा चुनाव के बाद देश के पहले बड़े चुनाव कहे जा रहे महाराष्ट्र व हरियाणा में मतदान हो गया। 24 अक्तूबर को साफ हो जाएगा कि भाजपा फिर सत्ता पर काबिज होगी या कांग्रेस का वनवास खत्म होगा। जो भी हो यह चुनाव मोदी सरकार की भी परीक्षा लेगा।

लोकसभा चुनाव के बाद देश के पहले बड़े चुनाव कहे जा रहे महाराष्ट्र और हरियाणा में मतदान हो गया। लोकसभा चुनाव में बंपर जीत हासिल करने वाली भाजपा और सहयोगी शिवेसना को महाराष्ट्र में एक बार फिर से सत्ता में वापसी की उम्मीद है। इसके साथ ही भाजपा हरियाणा में भी मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में एक बार फिर से वापसी के लिए मैदान में है। विपक्ष भले चुनाव प्रचार के दौरान उत्साहहीन नजर आया हो, लेकिन उसे ऐंटी-इन्कम्बैंसी फैक्टर से उम्मीद है। महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना ने तमाम मतभेदों को दूर करते हुए अंत में गठबंधन बनाकर उतरने का फैसला लिया था। दूसरी तरफ लंबे समय से साथी एनसीपी और कांग्रेस पूरे प्रचार के दौरान कमजोर नजर आए। पूरी कमान एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने ही संभाले रखी। राज्य के चुनावी समर में 235 महिलाओं समेत कुल 3,237 उम्मीदवार चुनावी समर में हैं। जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। हरियाणा की बात की जाए तो यहां भाजपा का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। हालांकि 90 सीटों वाले हरियाणा के कई इलाकों में इंडियन नेशनल लोक दल से अलग होकर बनी पार्टी जेजेपी मुकाबले को त्रिकोणीय बना चुकी है। 1.83 करोड़ मतदाता अपना फैसला दे चुके हैं कि खट्टर के नेतृत्व वाली सरकार फिर से सत्ता में लौटेगी या फिर कांग्रेस का वनवास खत्म होगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव में दोनों ही राज्यों में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की थी। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें है, जिनमें से सभी पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। इसके अलावा महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटों में से बीजेपी-शिवसेना गठबंधन ने 41 सीटों पर फतह हासिल की थी। ऐसे में माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी भगवा कैंप का पलड़ा भारी रह सकता है। दोनों ही राज्यों में वोटों की गिनती 24 अक्तूबर को होगी। चुनाव प्रचार की बात करें तो भाजपा की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कमान संभाली थी। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को भाजपा ने चुनाव का प्रमुख मुद्दा बनाए रखा। हालांकि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल किसी सटीक रणनीति पर चलते नहीं दिखे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हालांकि जरूर भाजपा शासित केंद्र और राज्य सरकारों पर इकोनॉमी के मोर्चे पर फेल होने को लेकर हमला बोला।

मगर वे भी जनता में असर छोड़ने में सफल नहीं रहे। सोनिया गांधी की चुनावी रैली भी निगती की रही। अब देखना यह है कि भाजपा की प्रचार शैली मतदाताओं पर कितना असर दिखा पाई है। जो भी हो 24 अक्तूबर को साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में भाजपा मोदी के नाम पर फिर सत्ता पर काबिज होगी या फिर कांग्रेस का वनवास खत्म होगा। जो भी हो यह चुनाव मोदी सरकार की भी बड़ी परीक्षा लेगा और उसके दूसरे कार्यकाल पर मुहर लगाएगा।

बिखरते परिवार और बुजुर्ग

सामान्य रूप में वरिष्ठ नागरिक की अवधारणा को तीन आयामों से समझा जा सकता है। पहला जैवकीय, अर्थात आयु के आधार पर, दूसरा मनोवैज्ञानिक अर्थात व्यक्तित्व में शामिल स्थिरता के आधार पर और तीसरा सामाजिक-सांस्कृतिक आयाम यानी उनके अनुभवों के आधार पर। ये तीनों पक्ष किसी भी बुजुर्ग के व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा होते हैं। इसलिए ये समूह समाज के लिए एक उत्पादक इकाई बने रहते हैं। ये अनुभवों को समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से नई पीढ़ी को इस आशा के साथ हस्तांतरित करते हैं कि अगर नई पीढ़ी उनके अनुभवों को अपने जीवन में प्रयुक्त करती चली जाएगी, तो उनके जीवन के जोखिम या खतरे कम होते जाएंगे। इसी वजह से इन्हें परिवार का मुखिया माना जाता है व परिवार में इनकी प्रतिष्ठा उच्च होती है। लेकिन अब प्रौद्योगिकी, संस्कृति और गतिशीलता में परिवर्तन के कारण परिवार नाम की संस्था की संरचना तेजी से बदल रही है। इस कारण बुजुर्ग अलगाव, अकेलेपन और पृथक्करण का शिकार तक हो रहे हैं। परिवार के कई सदस्य स्थानिक गतिशीलता के कारण घर से अलग दूसरी जगह जाकर रहने लगते हैं। परिणामस्वरूप संयुक्त परिवार में जो भूमिका यह पीढ़ी निभा रही थी, वही भूमिका अब पालना घर जैसी बाजार की संस्थाएं निभा रही हैं। परिवार में अब बच्चों के समाजीकरण का काम अब बाजार या तकनीक करने लगी है। संभवतः यही कारण है कि बच्चों में परिवार के प्रति भावनात्मक लगाव व सदस्यों के प्रति दायित्व की भावना नहीं पनपती। इसलिए ये पीढ़ी सामाजिक-आर्थिक असुरक्षा, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक असुरक्षा का शिकार हो रही है। यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक और आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में परिवार की भूमिका अब कम महत्वपूर्ण हो गई है। इसके लिए दोष किसे दिया जाए, यह एक चिंतन का विषय हो सकता है? परिवार समाज की नींव होता है, क्योंकि यह सामाजिक संगठन की आधारभूत इकाई है। पूर्व के समाजों में परिवार विस्तृत नातेदारी का एक हिस्सा हुआ करता था, जबकि आधुनिक समाजों में परिवार नातेदारों और संबद्ध समुदायों से कट गए हैं। इसके परिणामस्वरूप भावनात्मक तनाव परिवार का एक आवश्यक, लेकिन नकारात्मक अवयव बन कर उभरा है। यह भी सच है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं ने परंपरागत परिवारों के सामने अनेक संकट उत्पन्न किए हैं, जैसे तलाक की दर में वृद्धि, सहजीवन (लिव-इन-रिलेशनशिप), एकल अभिभावक परिवार, एक व्यक्ति परिवार इत्यादि। संभवतः ये परिवर्तन व्यक्तिवाद के बढ़ते प्रभाव को व्यक्त करते हैं जो परंपरागत परिवारों को चुनौती देते नजर आते हैं। इन परिवर्तनों ने समाज में असुरक्षा, अस्थिरता, तनाव को बढ़ावा दिया है और अब ये परिवारों में भी प्रवेश कर चुके हैं।

ज्यादातर बुजुर्ग घुट-घुट कर जीवन जीने को बाध्य हैं। यह आज के उपभोक्तावादी दौर का गंभीर परिणाम है। इसलिए परिवार में भय और हिंसा के पक्ष भी उभरे हैं। मनुष्य के मध्य संबंधों में अविश्वास उत्पन्न हुआ है, वह अलगाव का शिकार है, क्योंकि अमानवीय परिवेश इतना सघन रूप धारण कर चुका है कि वह किसी से भी अपनी इच्छाओं को साझा नहीं कर सकता। परिवार समाज की नींव होता है, क्योंकि यह सामाजिक संगठन की आधारभूत इकाई है।

आज ज्यादातर बुजुर्ग घुट-घुट कर जीवन जीने को बाध्य हैं। यह आज के उपभोक्तावादी दौर का सबसे गंभीर परिणाम है। इसलिए परिवार में भय और हिंसा के पक्ष भी उभरे हैं। मनुष्य के मध्य संबंधों में अविश्वास उत्पन्न हुआ है, वह अलगाव का शिकार है, क्योंकि अमानवीय परिवेश इतना सघन रूप धारण कर चुका है कि वह किसी से भी अपनी इच्छाओं को साझा नहीं कर सकता। देखा जाए तो एक तरफ तो समाज में स्वतंत्रता बढ़ी है, परंतु पहले की तुलना में व्यक्ति आज अधिक जकड़न में है क्योंकि उसके पास स्वाभाविक और स्वतंत्र जीवन जीने का समय ही नहीं बचा है। अविश्वास, धोखा, स्वार्थपरकता, भावनाओं का व्यवसायीकरण, प्रसिद्धि के द्वारा स्वयं को स्थापित करने की कोशिशें जैसे घातक पक्ष अब जीवन में शामिल हो चुके हैं। इसलिए वह इतना एकाकी है कि किसी पर भी भरोसा नहीं करता है, उसकी आंतरिक शक्ति समाप्ति हो चुकी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बुजुर्गों के खिलाफ अपराध में 4.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। साल 2016 में देशभर में वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ 21 हजार से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराधों के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है, जहां ऐसे कुल चार हजार 694 मामले सामने आए। मध्यप्रदेश (3,877), तमिलनाडु (2,895) और आंध्र प्रदेश (2,243) का स्थान आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार साठ वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या 104 करोड़ थी, जिनमें 51 करोड़ पुरुष और 53 करोड़ महिलाएं थीं। इनकी देखभाल के लिए सरकार और स्वंयसेवी संगठनों की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसकी उन्हें जानकारी भी नहीं होती। हाल के एक अध्ययन में सामने आया कि देश में 65 वर्ष की आयु से ज्यादा के 29 प्रतिशत लोग अकेले रहते हैं, योंकि इनके बच्चे या तो विदेश में रहते हैं या नौकरी की वजह से दूसरे शहरों में रह रहे हैं। इनमें से बहुत से बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनके आगे-पीछे कोई नहीं है। ऐसे में ये बुजुर्ग घर में अकेले रहने के दौरान या अकेले बाहर निकलते वक्त अपराधियों के लिए आसान निशाना होते हैं। परंपरागत परिवारों में वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा सदस्य को भावनात्मक समर्थन मिलता था। जब घर का कोई छोटा सदस्य या बच्चा अपने पेशे या नौकरी में निराशा और तनाव का सामना करता था तो बुजुर्ग उसके लिए सुरक्षा का कवच बन कर खड़े हो जाते थे। परिवार के वरिष्ठ सदस्य नई या युवा पीढ़ी के लिए परामर्शदाता की भूमिका निभाते थे। लेकिन तेजी से बदलते परिवेश ने उनकी इस भूमिका को हाशिए पर ला दिया है। समाज वैज्ञानिक मिशेल बैरेट तर्क देती हैं कि परिवार की अवधारणा में ऐसे तत्व भी होते हैं जो उसे समाज विरोधी बनाते हैं, क्योंकि यह महिलाओं के शोषण की वैधता को स्थापित करता है और परिवार के परिवेश के बाहर महिला के जीवन की किसी भी संभावना को समाप्त करता है। अतः परिवार के इस चरित्र को बदलने की जरूरत है। अर्थव्यवस्था का परिवार से घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था व्यक्तिवादी होती जा रही है, वैसे-वैसे परिवार में भी व्यक्तिवादिता का मूल्य बढ़ता जा रहा है। जब परिवार संस्था ही समाप्ति के कगार पर खड़ी हो तो समाज या सामाजिक संघटन के विघटन को कैसे रोका जा सकता है? परिवार प्रणाली में होने वाले इस विघटन को रोकने के लिए जरूरी है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को परिवार में शामिल किया जाए, लैंगिक समानता को स्थापित किया जाए, लड़के-लड़की को समान शिक्षा और मूल्य दिए जाएं, परिवार में संबंधों में ऊंच-नीच जैसे भेदभाव को समाप्त किया जाए, हर सदस्य एक-दूसरे का सम्मान करे, तकनीक या सोशल मीडिया पर निर्भरता को कम करके परिवार के सदस्यों को महत्व देने, भौतिक वस्तुओं की तुलना में मानवीय संबंधों को अधिक महत्व देने जैसे प्रयास जरूरी हैं। किसी भी राष्ट्र का मजबूत और कामयाब होना उसकी परिवार प्रणाली की मजबूती पर निर्भर करता है और परिवार की मजबूती वरिष्ठनागरिकों की भूमिका पर आश्रित होती है।

महंगी शिक्षा की सर्जरी की तैयारी

अगले दो दशकों में उच्च शिक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था के इंजन की तरह काम कर सकती है, बशर्ते कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए कतार में खड़े किसी भी योग्य उम्मीदवार को आर्थिक संसाधनों के अभाव में लौटाया न जाए। भारत में उच्च शिक्षा लगातार महंगी होती गई है। खास तौर पर तकनीकी और पेशेवर शिक्षा देने वाले अधिकांश संस्थान निजी क्षेत्र द्वारा संचालित किए जाते हैं, जिनकी मुय आय का साधन ट्यूशन फीस ही होती है। हमारे देश में मुफ्त उच्च शिक्षा और छात्रवृत्तियां न के बराबर हैं। इन हालात में लाखों गरीब और मध्यम वर्गीय विद्यार्थियों को शैक्षणिक कर्ज का सहारा लेना पड़ता है। पर अब सरकार इस समस्या का समाधान करने की दिशा में बढ़ चुकी है। कहा गया है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज शैक्षणिक सत्र 2020-21 से मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे। कॉलेजों की फीस पर लगाम कसने के लिए सरकार इसी हफ्ते फीस कमेटी गठित करने जा रही है। वहीं सरकार की मेडिकल डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कॉलेजों की फीस निर्धारण कमेटी ने रिपोर्ट में फीस कमेटी बनाने की सिफारिश की है। कमेटी ने सभी 126 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की फीस पर लगाम कसने वाला पहला डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी फीस रेगुलेशन भी बना दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक, मद्रास हाईकोर्ट ने मेडिकल डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की फीस पर लगाम लगाने संबंधी आदेश सरकार को दिया था। इसी के तहत यूजीसी ने मेडिकल डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की फीस पर लगाम लगाने संबंधी कमेटी गठित की थी। कमेटी ने इसी हफ्ते सरकार को अपनी रिपोर्ट दी है। कमेटी ने डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में मेडिकल के साथ-साथ इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट समेत सभी प्रोफेशनल संस्थानों को शामिल कर लिया है। इसमें सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं। यह नियम सभी प्रकार की 126 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी पर लागू होगा। महंगी उच्च शिक्षा न सिर्फ युवाओं के लिए आगे बढ़ने में बाधा है, बल्कि बैंकों के लिए भी नकसानदेह है। उच्च शिक्षा के लिए लोन लेने के बाद यह रकम कई बार बट्टेखाते में चली जाती है। इंडियन बैंस एसोसिएशन के अनुसार कुल शैक्षिक कर्ज का नौ प्रतिशत हिस्सा एनपीए में तब्दील हो जाता है। डिफॉल्टरों के सबसे ज्यादा 21 प्रतिशत मामले नर्सिंग व करीब 10 प्रतिशत इंजीनियरिंग कोर्सों के कर्जदारों के हैं। 2017 के एक आंकड़े के मुताबिक देश भर में एजुकेशन लोन की 6,356 करोड़ रुपए की रकम तीन लाख 45 हजार 340 बट्टा खातों (एनपीए) में जा चुकी है। देखा जाए तो उच्च शिक्षा हमारे संविधान की समवर्ती सूची का अंग है, जिसके बारे में कानून व नीतियां बनने का अधिकार केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को है। मोटे तौर पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों व राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के वित्तीय पोषण की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है।

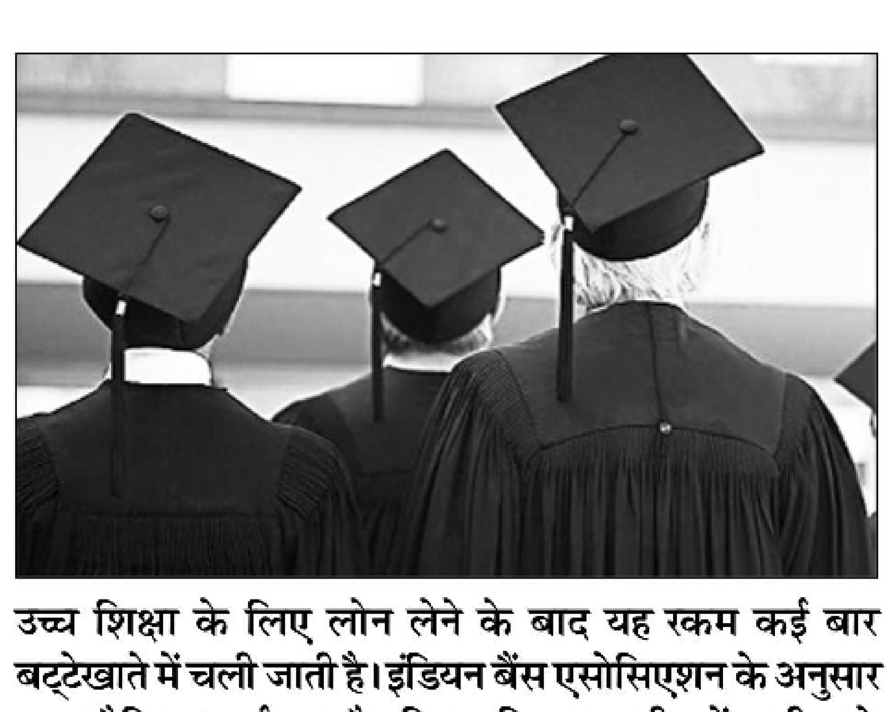

उच्च शिक्षा के लिए लोन लेने के बाद यह रकम कई बार बट्टेखाते में चली जाती है। इंडियन बैंस एसोसिएशन के अनुसार कुल शैक्षिक कर्ज का नौ प्रतिशत हिस्सा एनपीए में तब्दील हो जाता है। डिफॉल्टरों के सबसे ज्यादा 21 प्रतिशत मामले नर्सिंग व करीब 10 प्रतिशत इंजीनियरिंग कोर्सों के कर्जदारों के हैं।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at SARANGLE PRINTERS, BASTI GUZAN JALANDHAR (PUNJAB) and Published from ATUL SHARMA, NN-453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)

Editor: ATUL SHARMA*

*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.

BRO में मल्टी स्किल्ड वर्कर के 540 पदों पर भर्तियां

बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने मल्टी स्किल्ड वर्कर (ड्राइवर इंजन स्टेटिक) के पदों पर रिक्तियां निकाली हैं। इसके तहत कुल 540 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों पर सिर्फ पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन योग्य हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को डाक के माध्यम से आवेदन करना होगा। डाक से आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 24 नवंबर है। रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां इस प्रकार हैं-

मल्टी स्किल्ड वर्कर (ड्राइवर इंजन स्टेटिक), पद : 540 (अनारक्षित–221)

योग्तया : मान्यता प्राप्त स्कूली शिक्षा बोर्ड से दसवीं की परीक्षा पास होना चाहिए।

- इसके साथ ही मेकेनिक मोटर/व्हीकल्स/ट्रैक्टर ट्रेड में आईटीआई/इंडस्ट्रियल ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 25 वर्ष। अधिकतम आयु में एससी/एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष और ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

वेतन: 18,000 रुपए।

जरूरी सूचना: शैक्षणिक योग्यता से संबंधित अधिक ब्यौरे के लिए वेबसाइट देखें।

- अधिकतम आयु में एससी/एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।
- ओबीसी श्रेणी के आवेदकों को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

चयन प्रक्रिया: योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/स्किल टेस्ट/शारीरिक दक्षता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन शुल्क : सामान्य/ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 50 रुपए।

- एससी/एसटी और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं चुकाना होगा।
- शुल्क भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
- इससे संबंधित अधिक जानकारी पाने के लिए वेबसाइट पर लॉगइन करें।

आवेदन प्रक्रिया

- उम्मीदवारो को वेबसाइट (www.bro.gov.in) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज खुलने पर व्हाट्स न्यू सेक्शन में जाएं।
- इस सेक्शन में स्क्रॉल हो रहा Advt No 03/2019 लिंक नजर आएगा। इस पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही एक नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां पर pplications are invited for filling up the post of MSW DES in General Reserve Engineer Force लिंक दिया गया है।
- इस लिंक पर क्लिक करते ही रिक्तियों से संबंधित विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा। इसे अच्छी तरह से पढ़ें और पद के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें।
- इस विज्ञापन के साथ ही आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न किया गया है। इसका ए4 साइज के पेपर पर एक प्रिंटआउट निकाल लें।
- अब इसे ध्यान से पढ़कर पूरा भरें और इसके साथ मांगे गए प्रमाण पत्रों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी संलग्न करें।
- इसके बाद तैयार आवेदन पत्र को एक लिफाफे में डालें और उसके ऊपर साफ शब्दों में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ.....(आवेदित पद का नाम) लिखें। अब इस लिफाफे को डाक के माध्यम से तय पते पर भेजें।

यहां भेजें आवेदन पत्र

कमांडेंट जीआरईएफ सेंटर, दिघी कैंप, पुणे-411015

महत्वपूर्ण तिथि

डाक से आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि: 24 नवंबर 2019

अधिक जानकारी यहां

वेबसाइट : www.bro.gov.in

देश के प्रतिष्ठित संस्थानों या रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन करने वाले संस्थानों के स्नातक के विद्यार्थियों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इंटर्नशिप योजना 2019 की शुरुआत की है।

ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप कराएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय

साल में दो बार कराई जाएगी इंटर्नशिप

यह इंटर्नशिप भारतीय नागरिक और विदेश में बसे भारतीय नागरिक के लिए है। इस योजना के तहत कम से कम दो साल या चार सेमेस्टर पूरा कर चुके स्नातक के छात्रों को भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल विभाग और साक्षरता विभाग में दो महीने तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो कुछ छात्रों की इंटर्नशिप अवधि को छह महीने तक बढ़ा दिया जाएगा।

नीति निर्धारण प्रक्रिया के भागीदार बनेंगे विद्यार्थी

हालांकि जो छात्र नवंबर या दिसंबर 2019 तक स्नातक का कोर्स पूरा कर चुकेंगे, उन्हें भी इस इंटर्नशिप कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। इंटर्नशिप के लिए विधिवत रूप से भरे आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर है। मंत्रालय में अवर सचिव रत्नेश कुमार गुप्ता ने बताया कि इंटर्नशिप साल में दो बार कराया जाएगा। नवंबर/दिसंबर और अप्रैल/मई में होगा। इस योजना का मकसद युवा छात्रों को पारस्परिक लाभ के लिए नीति निर्धारण, परियोजना कार्यान्वयन और शिक्षा की विभिन्न पहलों के लिए सहयोगी बनने का अवसर प्रदान करना है।

15 स्थान इटर्नशिप के लिए उपलब्ध

इंटर्नशिप भारत सरकार के 15 विभागों या संस्थानों में कराया जाएगा। इंटर्नशिप के लिए एक इंटर्न को प्रति माह 10 हजार रुपए का सांकेतिक स्टाइपंड (प्रशिक्षण भत्ता) दिया जाएगा। इंटर्न को उसकी इंटर्नशिप सफलतापूर्वक समाप्त होने पर ब्यूरो द्वारा एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। उसे इंटर्नशिप के दौरान इंटरकॉम, टेलीफोन, इंटरनेट, लेखन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इंटर्न से अपेक्षित है कि वे संबंधित ब्यूरो को अपने असाइनमेंट के अंत में अपने अनुभव के बारे में संक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

कौन कर सकता है?

- तीन या चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में देश या विदेश में अध्ययनरत भारतीय और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारी विद्यार्थी।
- राष्ट्रीय महत्व और उत्कृष्ट संस्थानों के स्नातक विद्यार्थी।
- तकनीकी और प्रबंधन के वे विद्यार्थी जिनका संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग में 50 वीं रैंकिंग तक हो।
- विधि संस्थानों की श्रेणी में टॉप 10 संस्थानों के विधि में अध्ययनरत विद्यार्थी।
- नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 में 50वीं रैंक तक के संस्थानों के विद्यार्थी।
- वैश्विक स्तर पर 100वीं क्यू एस रैंकिंग में आने वाले संस्थानों के विद्यार्थी।

बगैर परीक्षा और इंटरव्यू दिए 10वीं पास के लिए निकली सरकारी नौकरी

भारतीय डाक ने बंपर वैकेंसी निकाली हैं। भारतीय डाक ग्रामीण डाक सेवक के 5 हजार 476 पदों पर भर्तियां करने वाला है। इंडिया पोस्ट ने तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश सर्किल के ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन तीनों सर्किलों के लिए कुल 5476 वैकेंसी निकाली गई है। आंध्र प्रदेश सर्किल में 2707, छत्तीसगढ़ सर्किल में 1799 और तेलंगाना में 970 वैकेंसी हैं। इन भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई हैं।

यहां जानें इस भर्ती से जुड़ी 10 अहम बातें

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 22 अक्टूबर से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन और फीस भुगतान की अंतिम तिथि 14 नवंबर है। एप्लाई ऑनलाइन मोड से ही करना होगा। इस भर्ती के जरिए ब्रांच पोस्ट मास्टर (बीपीएम), असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (एबीपीएम) और डाक सेवकों की भर्ती होगी।

योग्यता: 10वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। 10वीं में गणित और इंग्लिश विषय की पढ़ाई अनिवार्य है। इसके अलावा जिस सर्किल में आप आवेदन कर रहे हैं, वहां की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना भी अनिवार्य है।

आयु सीमा: न्यूनतम आयु सीमा: 18 वर्ष

अधिकतम आयु सीमा: 40 वर्ष

एससी, एसटी वर्ग को आयु में 5 वर्ष और ओबीसी को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

चयन: –कोई परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर होगा। मेरिट 10वीं में प्राप्तांकों के आधार पर बनेगी।

अगर किसी उम्मीदवार के पास हायर क्वालिफिकेशन है, तो यह कोई मायने नहीं रखेगा। सिर्फ 10वीं के मार्क्स ही चयन का आधार बनेंगे।

जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं indiapost.gov.in या appost.in/gdsonline पर जाकर रजिस्टर करें और यहीं से आवेदन करें।

सैलरी: चयनित होने वाले उम्मीदवारों को न्यूनतम 10,000 से 14,500 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा।

आवेदक को बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज और साइकिल चलाना भी आना चाहिए।

10वीं के मार्क्स का प्रतिशत 4 दशमलव बिंदु तक देखा जाएगा।

ज्यादा जानकारी के लिए adpsvco.cg@indiapost.gov.in पर मेल या 0771-2234591 पर संपर्क कर सकते हैं। आवेदन के लिए http://www.appost.in पर लॉग इन करें।

असिस्टेंट प्रोफेसर के 2331 पदों के लिए निकली भर्ती

इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा उम्मीदवारों का सेलेक्शन

तमिलनाडु सरकार, शिक्षक भर्ती बोर्ड, चेन्नई ने 2331 सहायक प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वह 30 अक्टूबर से पहले ऑनलाइन आवेदन करें। TRBTN भर्ती योग्यता / पात्रता की शर्तें, आवेदन कैसे करें और अन्य नियम नीचे दिए गए हैं।

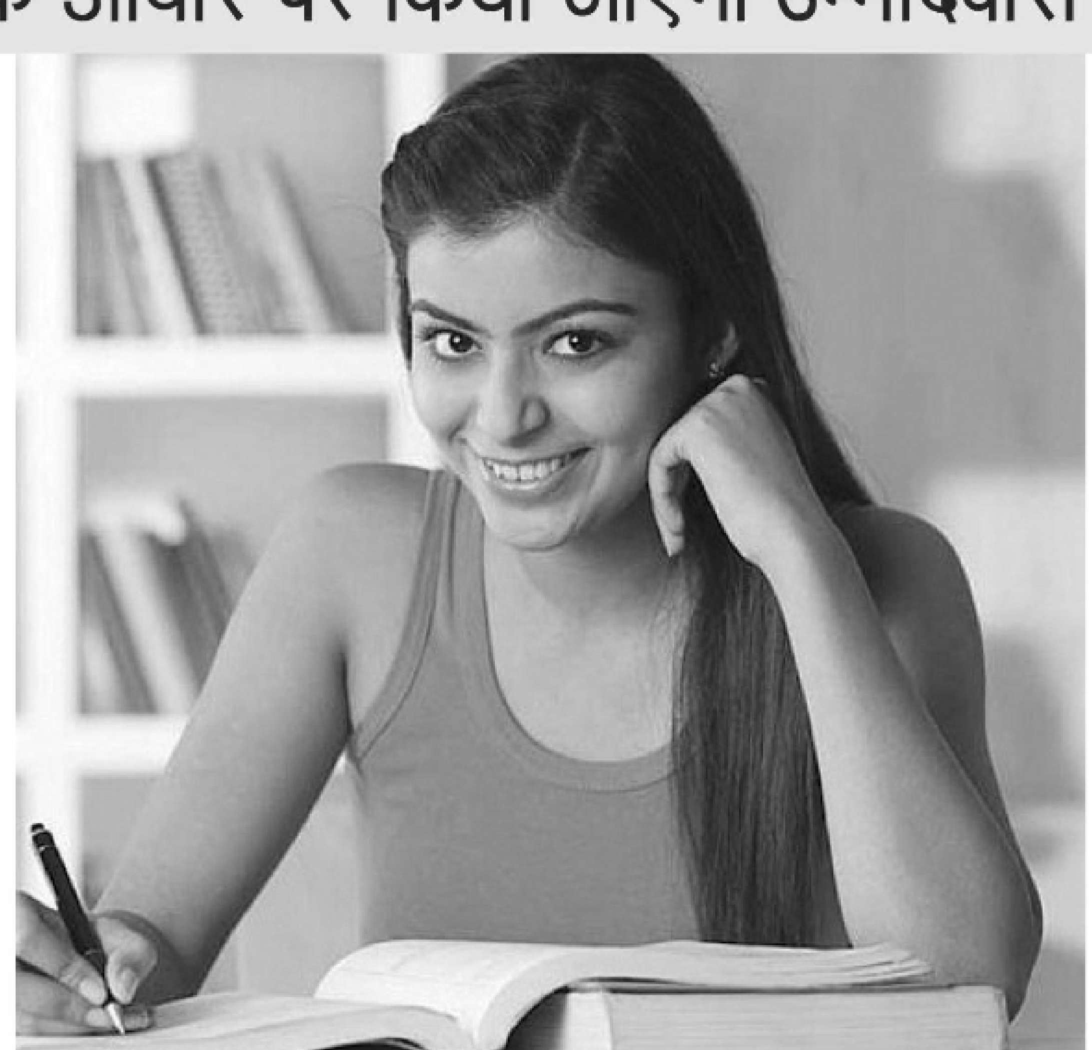

पदों का विवरण

तमिलनाडु सरकार, शिक्षक भर्ती बोर्ड ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 2331 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किए हैं।

योग्यता

किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएशन 55 प्रतिशत अंकों के साथ की हो। इसी के साथ यूजीसी नॉर्म्स के अनुसार NET / SLET / SET / SLST / CSIR / JRF परीक्षा पास की हो। उम्मीदवारों के पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए।

उम्र सीमा

01.07.2019 के अनुसार उम्मीदवार की उम्र 57 होनी चाहिए।

यह होनी चाहिए योग्यता

जनरल और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपए आवेदन फीस वहीं SC, SCA, ST / PWD उम्मीदवारों के लिए 300 आवेदन फीस है। उम्मीदवार आवेदन का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करें।

यह है जरूरी तारीख

आवेदन शुरू करने की तारीख: 4 अक्टूबर

आवेदन करने की आखिरी तारीख: 30 अक्टूबर

ऐसे करें आवेदन

उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट trb.tn.nic.in पर जाएं, बता दें नियुक्ति चेन्नई में होगी।

ऐसे होगा सेलेक्शन

उम्मीदवारों का सेलेक्शन शॉर्टलिस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

पे-स्केल

चुने गए उम्मीदवारों 57700 से 1,82,400 पे-स्केल तय किया गया है। अधिक जानकारी के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन देखें।

NIFT इंजीनियर के लिए निकली नौकरी, ऐसे भरना है आवेदन

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) ने इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर और अन्य पदों के लिए इच्छुक, योग्य उम्मीदवारों को आमंत्रित करते हुए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए आवेदन मांगे हैं। सभी उम्मीदवार 29 अक्टूबर को या उससे पहले आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करने के इच्छुक हैं वह नीचे दी गई जानकारी पढ़ लें।

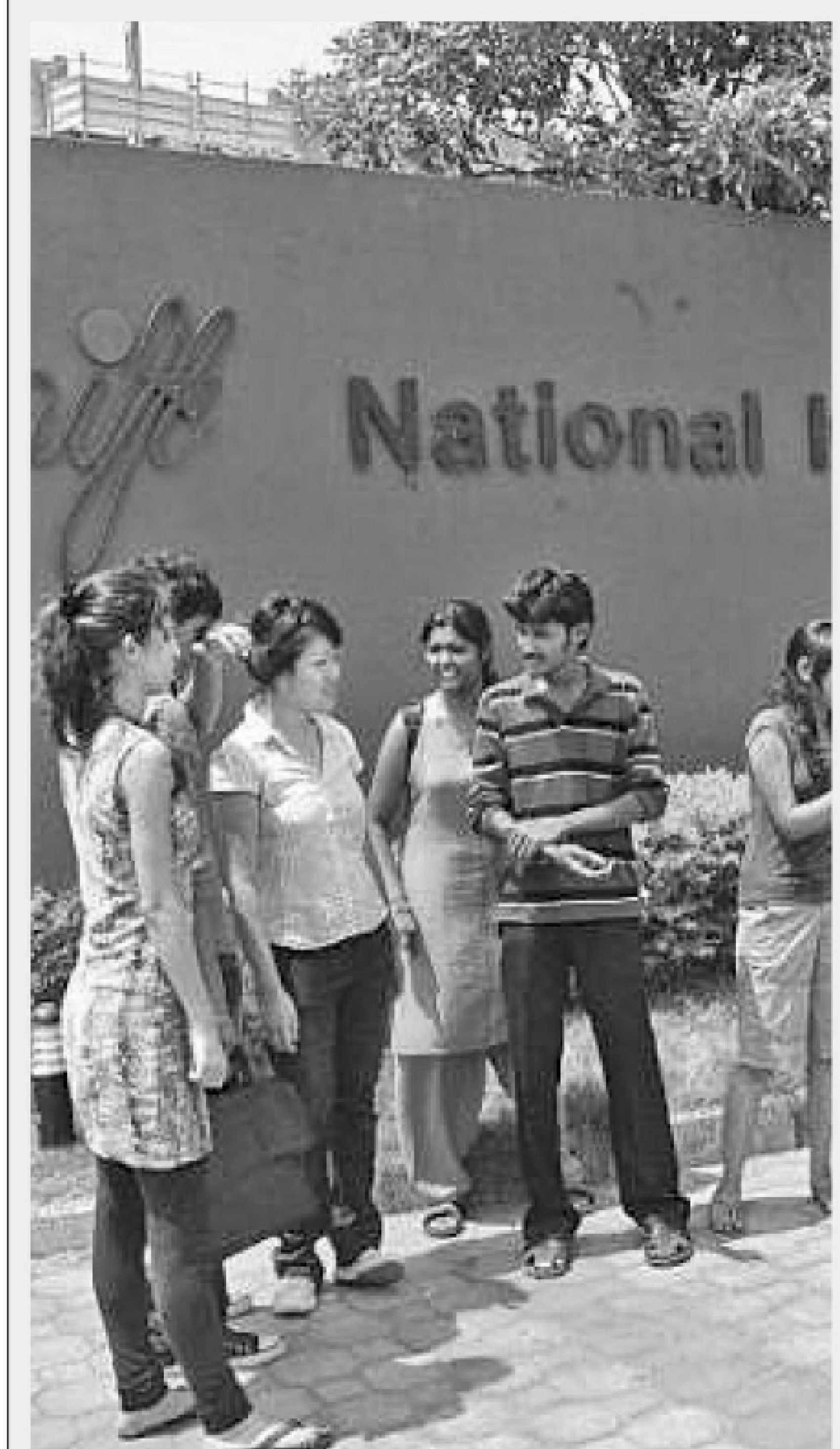

पदों की संख्या

इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर के लिए 30 पद खाली हैं। पदों की संख्या कम है, ऐसे में उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन करें।

यह है पदों के नाम

जूनियर इंजीनियर (सिविल): 6 पद

जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल): 10 पद

असिस्टेंट डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन: 1 पद

कंप्यूटर इंजीनियर: 13 पद

ऐसे करें आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले NIFT की आधिकारिक वेबसाइट nift.ac.in पर जाएं।
स्टेप 2- 'Careers @ NIFT' पर क्लिक करें।
स्टेप 3- 'Apply online' पर क्लिक करें।
स्टेप 4- अपना लॉग इन अकाउंट क्रिएट करें।
स्टेप 5- मांगी गई सारी डिटेल्स भरें।
स्टेप 6- अब फीस का भुगतान करें।
स्टेप 7- सबमिट करें, भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें।

एप्लीकेशन फीस

असिस्टेंट डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन: 10,000 रुपए

कंप्यूटर इंजीनियर/जूनियर इंजीनियर: 500 रुपए

आरक्षित श्रेणी: कोई फीस नहीं है।

यह है योग्यता

असिस्टेंट डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन: उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ME/MTech/MCA की डिग्री ली हो।
कंप्यूटर इंजीनियर: BE/BTech में कंप्यूटर साइंस में डिग्री ली हो।
जूनियर इंजीनियर: सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा लिया हो।

उम्र सीमा

जूनियर इंजीनियर (सिविल): अधिकतम उम्र 40 साल

जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल): अधिकतम उम्र 35 साल

असिस्टेंट डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन: अधिकतम उम्र 35 साल

कंप्यूटर इंजीनियर: अधिकतम उम्र 35 साल

यह है अंतिम तिथि

आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। यह सभी जानकारी के लिए भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन देख सकते हैं।

गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही आयुष्मान भारत योजना:आनंदीबेन

■ अमेठी/ब्यूरो

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के तहत बच्चों को तरजीह देने पर जोर देते हुए कहा कि एक सर्वेक्षण कराने की जरुरत है ताकि गम्भीर रूप से बीमार बच्चों को समुचित इलाज मिल सके। आयुष्मान भारत योजना के तहत केन्द्र सरकार गरीबों को स्वास्थ्य बीमा देती है। इसके पात्र व्यक्ति को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ अमेठी के दौरे पर आयीं राज्यपाल ने कहा कि केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। अमेठी के मलिक मोहम्मद जायसी जिला अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्रों को गोल्डन कार्ड वितरित करने के बाद अपने सम्बोधन में राज्यपाल ने कहा कि ऐसी योजनाओं से समाज और देश मजबूत होता है। इस योजना से एक साल मे पांच लाख रुपये के इलाज की सुविधा मिल रही है। जनता को इसका लाभ उठाना चाहिये।राज्यपाल ने कहा कि इस योजना के प्रचार–प्रसार की जरूरत है। जो भी अस्पताल इस योजना के तहत इलाज के लिए चयनित हैं, उनके बाहर बड़े बोर्ड लगाकर योजना के संबंध में जानकारी दी जानी चाहिये।आनंदीबेन ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और मरीजों से इलाज की व्यवस्था के विषय में जानकारी ली। उन्होंने परिसर में पौधरोपण भी किया।राज्यपाल एवं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गौरीगंज में स्थित वृद्धा आश्रम का निरीक्षण किया तथा सुविधाओं के विषय में लोगों से जानकारी ली।

कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, अब नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने छोड़ी पार्टी

■ अमृतसर/ब्यूरो

कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पंजाब सरकार में पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दी है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वह अब किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ने वाली हैं। हालांकि नवजोत कौर पंजाब के लिए सोशलवर्कर के तौर पर अपनी लड़ाई जारी रखेंगी। वेरका में एक कार्यक्रम में पहुंची नवजोत कौर ने ऐलान किया कि वह अब कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रही हैं। आपको बता दें कि नवजोत कौर अकाली दल–भाजपा की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी हैं।

पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने कहा कि अब उनका मुख्य लक्ष्य अमृतसर पूर्वी हलके का विकास करना है और वह इसके लिए जी–जान लगा देंगी। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि यदि उन्हें उनके हलके का विकास करने के लिए पैसा न दिया गया तो वह सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगी।

पंजाब सरकार द्वारा बदला जायेगा ग्रामीण डिसपैंसरियों का रूप, 460 मैडीकल अफसरों की भर्ती जल्द–तृप्त बाजवा

ग्रामीण डिसपैंसरियों के लिए 48 लाख की दवाओं की सप्लाई, अगले तीन महीनों के लिए 2.58 करोड़ की दवाएँ खरीदी जाएंगी

■ चंडीगढ़/विजय कुमार

पंजाब सरकार द्वारा गाँवों के लोगों को बढ़िया स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए गाँवों की डिसपैंसरियों के लिए सभी ज़रूरी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। आज यहाँ जारी बयान में रा%य के ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री स. तृप्त रजिन्दर सिंह बाजवा ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब सरकार द्वारा जल्द ही 460 मैडीकल अफसरों की भर्ती की जायेगी, जिसके लिए विभाग ने कार्यवाही शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि इस कार्यवाही को जल्द पूरा करने के लिए विभाग के सीनियर अधिकारियों को स्पष्ट हिदायतें जारी की गई हैं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री ने साथ ही कहा कि गाँवों की डिसपैंसरियों में दवाएँ और अन्य ज़रुरी सामान की कोई कमी नहीं आने दी जायेगी। उन्होंने बताया कि 48.30 लाख रुपए से अधिक की दवाओं की खरीद करके गाँवों की डिसपैंसरियों में भेज दी गई हैं। इसके अलावा अगले तीन महीनों के लिए 2.58 करोड़ की दवाएँ खरीदने के लिए ऑर्डर दिया जा रहा है।

स. बाजवा ने विभाग के सीनियर अफसरों को हिदायतें जारी करते हुए कहा कि गाँवों के लोगों को डिसपैंसरियों में बढ़िया स्वास्थ्य सुविधाएं यकीनी बनाने के लिए पूरी निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि डिसपैंसरियों का स्टाफ समय पर ड्यूटी पर अपनी हाज़िरी यकीनी बनाए और मरीजों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने गाँवों की डिसपैंसरियों का रूप बदलने संबंधी विभाग के अधिकारियों को एक प्रोजैक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा जिससे गाँवों के लोगों को ग्रामीण डिसपैंसरियों में और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

सुखजिन्दर सिंह रंधावा ने करतारपुर गलियारे की प्रगति और प्रबंधों का जायज़ा लिया

सहकारिता मंत्री ने डेरा बाबा नानक उत्सव की अधिकारित वैबसाईट जारी की

■ चंडीगढ़/विजय कुमार

श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शनों के लिए खुल रहे करतारपुर गलियारे की प्रगति और किये जाने वाले प्रबंधों का जायजा लेने के लिए आज सहकारिता और जेल मंत्री स. सुखजिन्दर सिंह रंधावा ने यहाँ उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग की।

मीटिंग के उपरांत विवरण जारी करते हुए स. रंधावा ने बताया कि 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर करतारपुर गलियारा खुलना समूची नानक नाम लेवा संगत के लिए ऐतिहासिक पल है जिसको यादगार बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जायेगी। उन्होंने कहा कि भारत वाली तरफ गलियारे का निर्माण काम तकरीबन मुकम्मल होने वाला है और 31 अक्तूबर तक हर हाल में काम मुकम्मल हो जायेगा। नवबंर महीने गलियारे के उद्घाटन के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि करतारपुर गलियारे के खुलने के कारण डेरा बाबा नानक में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में अभी से ही वृद्धि हो गई है। संगतों की बड़ी आमद को देखते हुए प्रशासन को कोई भी कसर न छोड़ने के आदेश दिए हैं। सहकारिता मंत्री ने बताया कि 8 से 11 नवंबर तक मनाए जाने वाले डेरा बाबा नानक उत्सव की तैयारियों की भी समीक्षा की गई जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु डेरा बाबा नानक आऐंगे। इस अवसर पर उन्होंने डेरा बाबा नानक उत्सव की अधिकारित वैबसाईट भी जारी की। मीटिंग में अतिरिक्त मुख्य सचिव सहकारिता श्रीमती कल्पना बरूहा मित्तल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री तेजवीर सिंह, रजिस्ट्रार सहकारी सभाएं श्री विकास गर्ग, मार्कफैड के एम.डी. श्री वरुण रूज़म, मिल्कफैड के एम.डी. श्री कमलदीप सिंह संघा, गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर श्री विपुल उज्जवल, मार्कफैड के एडीशनल एम.डी. श्री राहुल गुप्ता, पंजाब राज्य कृषि विकास बैंक के एम.डी. श्री चरनदेव सिंह मान, पंजाब राज्य सहकारी बैंक के एम.डी. डा.एस.के. बातिश और डेरा बाबा नानक उत्सव के कोऑर्डीनेटर श्री अमरजीत सिंह गरेवाल भी उपस्थित थे।

जिला प्रशासन ने जालंधर निवासियो को 2021 तक 24X7 घंटे पानी सप्लाई के लिए कसी कमर

जिलाधीश और एमसी कमिश्नर ने 2021 तक इस काम को पूरा करने के लिए बैठक की

■ जालंधर/नीरज

एक प्रमुख कदम उठाते हुए, जिला प्रशासन ने आज जालंधर शहर के निवासियों के लिए वर्ष 2021 तक 24X7 पानी स्पलाई देने के लिए कमर कसी ।

जिला प्रशासकीय परिसर में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए, जिलाधीश जालंधर श्री वरिंदर कुमार शर्मा के साथ नगर निगम जालंधर के कमिश्नर श्री दीपरवा लाकड़ा ने कहा कि जमीन के नीचे जल स्तर को कम करने के लिए आदमपुर के पास जालंधर सिंचाई नहर से जालंधर निवासियों को जल स्पलाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे चरण में 275 मिलियन लीटर प्रति दिन (MLD) और 90 MLD की क्षमता वाला एक वाटर ट्रीटमेंट

प्लांट स्थापित किया जाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि 275 MLD वर्ष 2036 तक शहर की जरूरतों को पूरा करेगा और अतिरिक्त 90 MLD 2051 तक शहर के निवासियों की आवश्यकता को पूरा करेगा। जिलाधीश और नगर निगम कमिश्नर ने कहा कि पहले चरण में शहर के निवासियों को प्रतिदिन 113 क्यूसिक पानी की आपूर्ति की जाएगी, ताकि उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 2036 तक और बाद में 2051 तक इसे 149 क्यूसिक तक बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि कुल परियोजना की लागत लगभग 890 करोड़ रुपये थी और इस परियोजना के लिए 100 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 66 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी और दूसरे चरण में 34 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। जिलाधीश और नगर निगम कमिश्नर ने कहा कि भूमि का उपयोग जल उपचार संयंत्र और पानी की आपूर्ति के लिए अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने तीन गांवों में जमीन को अंतिम रूप दे दिया है । इस समय नगर निगम जालंधर दिन में 8–12 घंटे 1,52, 844 दर्ज किए गए घरों में पानी की आपूर्ति करता है। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी श्री जितेन्द्र जोरवाल ,सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट डा जय इंद्र सिंह, जिला राजस्व अधिकारी श्री जशनजीत सिंह, मुख्य अभियंता जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड श्री हरजिंदर सिंह, कार्यकारी अभियंता श्री जतिन वासुदेव, उप विभागीय अधिकारी श्री गगन और अन्य भी उपस्थित थे।

पंजाब सरकार द्वारा महिला आयोग को मज़बूत करने की दिशा में एक और कदम

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए पंजाब राज्य महिला आयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक और कदम उठाया है।

इस संबंधी जानकारी देते हुए आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब सरकार के दिशा निर्देश पर पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल अमरदीप सिंह राय ने आयोग की चेयरपर्सन श्रीमती मनीषा गुलाटी को एक अर्ध सरकारी पत्र के द्वारा लिखा है कि जब भी पंजाब राज्य महिला आयोग, पंजाब सरकार के ध्यान में किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कोई शिकायत लाता है और आयोग समझता है कि अधिकारी ने कोई कोताही की है, तो तुरंत इस कार्यालय के नोटिस में लाया जाये जिससे अधिकारी के विरुद्ध बनती कार्यवाही की जा सके और बदलियां/तैनातियों के समय ध्यान में रखा जा सके।

किडनी को बचाना है तो पैदल मार्च और कसरत जरूरी

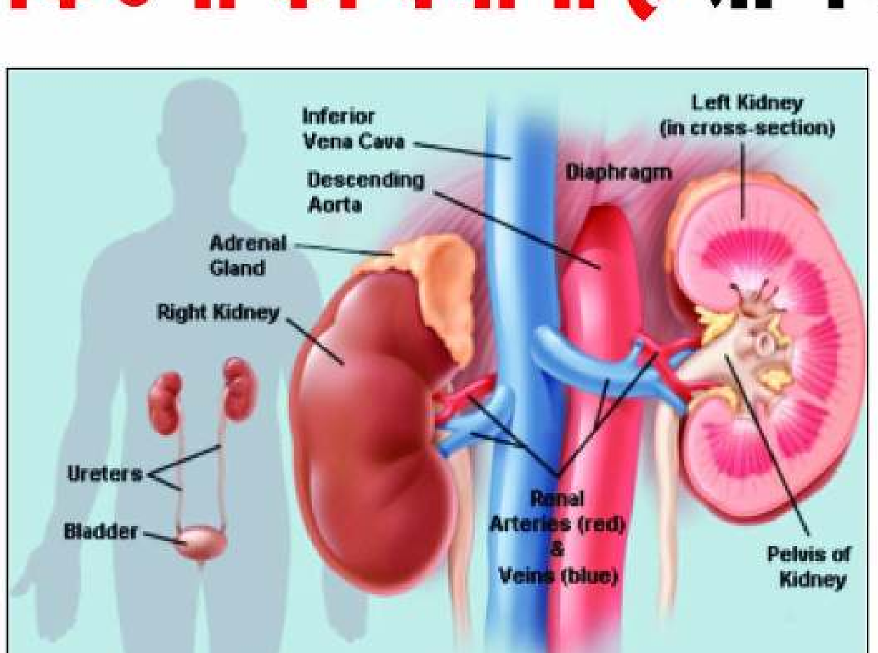

जालंधर से नीरज की विशेष रिपोर्ट

किडनी और दिल बचाना है तो दौड़ भाग तो करनी होगी। किडनी के रोगों में अब कई नये ट्रैंड भी देखने को मिल रहे है। खेतों मे कीटनाशक डालने वाले किसान और बिना प्रमाण वाली भस्मों का इस्तेमाल करने वाले मरीजों में किडनी फेल के मामले बढते जा रहे है। यूं तो ज्यादातर किडनी फेल होने के मामले उन मरीजों में देखे जाते है जिन्हें शूगर और बीपी की बीमारी होती है, लेकिन अब कई मामले एसे भी सामने आ रहे है जिनमें मरीज लंबे समय तक झोलाछाप डाक्टरों से दवा लेते है और अब जब पेनकिल्लर या अप्रमाणिक भस्में किडनी खराब कर बैठे है। जालंधर के पठानकोट रोड स्थित श्रीमन सुपर स्पैशिएलिटी अस्पताल में शनिवार को देश भर के किडनी स्पेशलिस्ट पहुंचे थे। मौका था रीनल पैथोलाजी (किडनी की बायोप्सी) पर साइंटिफिक प्रोग्राम। इसमें मेदांता किडनी इंसिट्टयूट के डायरेक्टर डा राज कुमार शर्मा ने बताया कि अब कीटनाशकों के इस्तेमाल करने वाले किसानों में किडनी फेल के केस भी मिलने लगे हैं। यह आधुनिकता के साइड इफे1ट हैं।

किडनी फेल होने के कुछ अन्य कारण

1.साथ ही हमारे देश में तापमान का कभी बहुत ज्यादा हो जाना और कभी सर्दियों में बहुत कम हो जाना। यह तापमान की फ्लक्चुएशन भी किडनी फेल के मामले पढ़ा रही है।

2.कुछ मामलों में देसी दवा का इस्तेमाल भी घातक साबित होता है। बहुत सारी देसी दवाइयों में बस्म का इस्तेमाल होता है। कई गैर प्रमाणिक भस्मों में हैवी मेटल होते है। उन हैवी मेटल से भी किडनी डैमिज हो सकती है।

3.कुछ एसे लेप बी है जिन्हें जब लोग पूरे शरीर पर लगाते है तो वह त्वचा से होते उए शरीर में दाखिल हो जाती है। यानी घटिया क्रीम या लेप भी किडनी को डैमेज कर सकती है।

बचाव

डा. राज कुमार ने बताया कि बहुत ही कम पैसों से दो टेस्ट करवाने से किडनी के रोगों का पता लग सकता है। खासकर 50 की उम्र पार कर चुके और शुगर बीपी के मरीजों को साल मे कम से कम एक बार तो खून में क्रेटनीन और यूरिन में प्रोटीन के टैस्ट करवा लेने चाहिए। ये टैस्ट बहुत सस्ते भी है और इनसे किडनी की सेहत का काफी हद तक अंदाजा लग जाता है। असल में किडनी के रोग अपने लक्षण बहुत देरी से दिखाते है। जब तक लक्षण सामने आते है तब तक किडनी का काफी हिस्सा डैमेज हो चुका होता है साथ ही दिल को भी स्वस्थ रखें। अगर किसी को हार्ट की समस्या है तो उसे किडनी की समस्या होने का बी खतरा है और जिसे किडनी की समस्या है उसे हार्ट की समस्या होने का भी डर बना रहता है। ऐसे में खुद को फिट रखें।

मोटर गडीयां छडो पैदल चलण नाल आपणा आप बचाओ- डा. भाटिया

श्रीमन के किडनी विभाग के एचओडी और सीनियर नेफ्रोलोजिस्ट डा राजीव भाटिया के साथ बात की। उन्होने एक लाइन मे बताया कि मोटर गडीयां छडो पैदल चलो, इसी से सेहतमंद रह सकते है। डा भाटिया ने बताया कि 80 प्रतिशत किडनी फेल्योर के मामले बीपी और शूगर के मरीजों में से है। बाकी के 20 प्रतिशत दूसरी बीमारियों के है। लोग उन 80 प्रतिशत में आने से खुद को तभी रोक सकते है जब वह अपने जीवन में बदलाव लेकर आएंगे। डाक्टर और पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि अपने शरीर से काम लेना शुरू करो। ज्यादा से ज्यादा पैदल जलो। रोज कसरत करो। सुबह शाम सैर करो। खाने पाने की बुरी आदतों को छोडो। मगर लोग सब जानते हुए भी अपने आलस भरे जीवन को त्यागने में बिलकुल भी रूचि नही दिखा रहे। जब वक्त बीत जाता है तब बिमारियां घेर लेती है। इसलिए आज ही अपने जीवन में बदलाव लाए।

योग सैर खेलकूद में हिस्सा लें

योग, सैर, कसरत, खेलकूद में हिस्सा लेना शुरू करें। फास्टफूड को छोडकर फल और सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करें। तन और मन स्वस्थ बनाएं।

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
CONSULTING | DESIGN | TRAINING

ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

IELTS • PTE • TOEFL
SPOKEN ENGLISH

TOURIST VISA | STUDY VISA | PR
WORK PERMIT | HOLIDAY PACKAGES

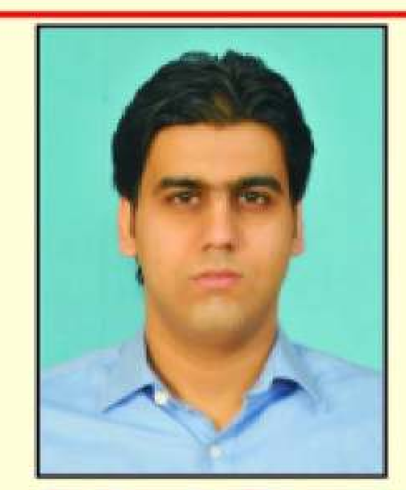

Ankush Sharma
Chartered Engineer
Alumni M.S.(Software Engineering), BITS Pilani

9988115054 • 9317776663

REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10, Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal.

HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza, GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.

E-mail : ankush@innovativetechin.com • hr@innovativetechin.com

Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin